International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.379 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 6, November 2022 |

भारत में महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण

Desh Raj Gurjar

Assistant Professor, Govt. College Kathumar, Alwar, Rajasthan, India

सार

कौशल विकास की जरूरत पर बल देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में उल्लिखित विश्वकर्मा योजना प्रमुख भूमिका निभायेगी और वह एक सेतु के रूप में काम करेगी। उसके अवसरों का इस्तेमाल महिला सशक्तिकरण के लिए किये जाने की जरूरत है। इसी तरह, जी-ई-एम और ई-वाणिज्य महिलाओं के व्यापार अवसरों को विस्तार देने का माध्यम बन रहे हैं।

परिचय

महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी हैं, जब अधिक महिलाएं काम करती हैं, तो इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सकारात्मक विकास परिणामों और उत्पादकता को बढ़ाता है, इसके आलावा यह आर्थिक विविधीकरण और आय समानता को भी बढ़ाता है।

महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को फलीभूत करने के लिए महिला आर्थिक सशक्तिकरण Women Economic Empowerment केंद्रीय आवश्यकता है। महिला उद्यमियों के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से उनकी सफलता की यात्रा के लिए अधिक सहयोग और अवसर प्रदान करना समय की मांग है।

वर्तमान में, भारत में लगभग 432 मिलियन कामकाजी महिलाएं हैं, जिनमें से 343 मिलियन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट McKinsey Global Institute की एक रिपोर्ट ने अनुमान लगाया है कि महिलाओं को समान अवसर देकर, भारत 2025 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में 770 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ सकता है। भारतीय स्टार्टअप दृश्य एक महत्वपूर्ण बदलाव देख रहा है क्योंकि महिला उद्यमी बाधाओं को तोड़ती हैं और अपनी पहचान स्थापित करती हैं। एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के लगभग 18 % यूनिकॉर्न अब महिलाओं द्वारा स्थापित किए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास (Women Empowerment and Economic Development) एक-दूसरे से बड़े घनिष्ट रूप से संबंधित हैं: या अगर यू कहें की एक दूसरे के पूरक है तो ये कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी, क्योंकि आत्मनिर्भरता सशक्तिकरण की पहली शर्त है। आत्मनिर्भर आने से ही सशक्तिकरण संभव होता है और इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन स्तर में सुधार पर पड़ता है।[1]

जब तक आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है तब तक आप आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकते। जिसके लिए आर्थिक रूप से आपकी निर्भरता ख़त्म होनी पहली आवश्यकता है।

भारत एक ऐसा देश है जहाँ समाज पुरुष प्रधान रहा है और यहाँ महिलाओं की परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भरता उनके जीवन के लगभग हर क्षेत्र में देखी गई। कुछ हद तक, परिवार में महिलाओं की निम्न स्थिति और निर्णय लेने की कमी के लिए पुरुषों पर उनकी आर्थिक और सामाजिक निर्भरता को जिम्मेदार माना जाता है।

महात्मा गांधी जी ने 'यंग इंडिया' (Young India by Mahatma Gandhi) नामक एक साप्ताहिक पत्रिका में 1930 में लिखा था की "हमारे गांवों में लाखों महिलाएं जानती हैं कि बेरोजगारी का क्या मतलब है, उन्हें आर्थिक गतिविधियों तक पहुंच प्रदान करें जिससे वो अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को जान सकेगी, जिससे वह अब तक अनजान रही हैं"

लगभग एक सदी बीत चुकी है, और भारत ने तब अब तक सभी क्षेत्रों में बहुआयामी विकास हासिल किया है, उसके बावजूद आज भी बहुत सी समस्याएं प्रासंगिक हैं। हालांकि, महिलाएं भारत की 1.2 अरब की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, फिर भी उन्हें आर्थिक गतिविधियों (economic activities) और निर्णय लेने की स्वतंत्रता (decision making freedom) के साथ ही स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आदि के संसाधनों तक भी आसानी से पहुंच प्रदान नहीं है। [2]

भले ही कामकाजी महिलाओं (working women) की संख्या लगभग 432 मिलियन है, लेकिन उनमें से लगभग 343 मिलियन वेतन वाली औपचारिक नौकरी में नहीं हैं। उनमें से लगभग 324 मिलियन श्रम बल में नहीं हैं; और अन्य 19 मिलियन श्रम शक्ति का हिस्सा हैं लेकिन नियोजित नहीं हैं।

इसलिए, महिलाओं के रोजगार की प्रकृति का औपचारिक अर्थव्यवस्था में हिसाब नहीं रखा जाता है, या फिर महिलाओं को वर्तमान सामाजिक-सांस्कृतिक जटिलताओं के कारण औपचारिक नौकरियों तक पहुंच ही प्राप्त नहीं होती है।

भारत जैसे देश में जहां गहरी पितृसत्ता (deep patriarchy) वाले समाज के रूप में, भले ही महिलाएं रोजगार प्राप्त करना चाहती हों, लेकिन दूषित और रूढ़िवादी सामाजिक सोच के कारण महिला घरेलू जिम्मेदारी की प्रमुख वाहक के रूप में मानी जाती हैं। और यही सोच उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में उनकी आर्थिक उन्नति और अवसरों (economic growth and opportunities) तक पहुंच को सीमित करती है।

इस तरह के परिदृश्य में, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) Self Help Groups (SHGs) उन महिला उद्यमियों के बीच एक ब्रिज के रूप में कार्य कर रहे रहे हैं जिनके पास अपना उद्यम शुरू करने की इच्छा है, लेकिन उनके पास अपने सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन और माहौल नहीं हैं।

एक एसएचजी में महिलाओं का एक छोटा समूह शामिल होता है जो नियमित रूप से मौद्रिक योगदान देने के लिए एक साथ आते हैं। स्वयं सहायता समूह ऐसी महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं जो महिलाओं के बीच एकजुटता को बढ़ावा देते हैं, उन्हें स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के मुद्दों पर न सिर्फ जागरूक करते है बल्कि संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराते है ।[3]

विचार-विमर्श

महिलाएं देश की आधी आबादी है जब अधिक महिलाएं काम करती हैं, तो इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण, सकारात्मक विकास परिणामों के अलावा उत्पादकता को बढ़ाता है, इसके साथ ही आर्थिक विविधीकरण और आय समानता को भी बढ़ाता है।

महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को फलीभूत करने के लिए महिला आर्थिक सशक्तिकरण केंद्रीय आवश्यकता है। इसमें मौजूदा बाजारों में समान रूप से भाग लेने की महिलाओं की क्षमता; उत्पादक संसाधनों (productive resources) तक उनकी पहुंच और नियंत्रण, अच्छे कामों तक पहुंच, अपने समय, जीवन और शरीर पर नियंत्रण; और घर से लेकर अंतरराष्ट्रीय संस्थानों तक सभी स्तरों पर निर्णय लेने में उनकी सक्रीय और सार्थक भागीदारी शामिल है ।

महिलाओं ने बीते दशकों में स्वयं को आत्मनर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये है। महिलाये सांगठनिक स्तर पर अधिक मजबूती से आगे बढ़ रही है। उनके सामूहिक प्रयास बड़े पैमाने पर सामाजिक,आर्थिक और काफी हद तक राजनैतिक परिदृश्य पर बड़े बदलाव के साक्षी बन रहे है। महिलाये संगठित हो कर ही अपनी दिशा और दशा बदल सकती है, ये बात वो समझ चुकी है।

शुरुआत में औपचारिक रूप से संचालित समूहों ने समय के साथ अपनी पहचान बनाई और बाद में सरकार ने भी इसकी महत्ता और शक्ति को समझते हुए औपचरिक स्वरुप प्रदान कर इन्हे मान्यता दी और प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न योजनाओं से जोड़ते हुए इन्हे और अधिक सशक्त करने हेतु प्रयास तेज किये। इसी के साथ देश में स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा ने जन्म लिया और इससे महिलाओं को सांगठनिक स्तर पर एकजुट होकर अपने सर्वांगीण विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। [5]

स्वयं-सहायता समूह का मतलब ऐसे लोगों के स्वयं-शासित, समकक्ष नियंत्रित, अनौपचारिक समूह से है, जिनकी समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि हो और सामूहिक रूप से कार्य करने की इच्छा रखते हों। भारत में, SHG आंदोलन 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब कई गैर-सरकारी संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब समुदायों को संगठित किया और उन्हें सामाजिक और वित्तीय सहायता के लिए औपचारिक चैनल की पेशकश की।

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (National Bank for Agriculture and Rural Development) के साथ इस कार्यक्रम ने गति प्राप्त की, ऐसे समूहों की एक छोटी संख्या को बैंकों के साथ जोड़ा गया। स्वयं-सहायता समूह द्वारा बैंक लिंकेज कार्यक्रम चलाया है, इस क्रांतिकारी पहल ने समूह के सदस्यों को जोड़ा, जिनमें से कई के पास पहले कभी बैंक खाते नहीं थे।

भारत में स्वयं सहायता समूहों की उत्पत्ति का प्रथम प्रमाण 1972 में स्व-नियोजित महिला संघ (सेवा) Self Employed Women's Association (SEWA) की स्थापना से मिलता है । इससे पहले भी संगठन के छोटे-छोटे प्रयास होते थे। उदाहरण के लिए, 1954 में, अहमदाबाद के टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (टीएलए) Textile Labor Association (TLA) ने इसी क्रम में अपनी महिला विंग का गठन किया, जो एक ऐतिहासिक आंदोलन का प्रतीक है, जिसमे महात्मा गांधी की भूमिका प्रमुख रही।

सेवा का गठन करने वाली इला भट्ट (Ela bhatt) ने गरीब और स्वरोजगार करने वाली महिला कामगारों को संगठित किया। नाबार्ड ने 1992 में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट (SHG Bank Linkage Project) का गठन किया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ी सूक्ष्म वित्त परियोजना।

आज बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूहों की स्थापना हो रही है और इसे एक वैधानिक इकाई (statutory entity) का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को निर्वाह से स्थिरता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया और जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी भारत के सबसे शक्तिशाली माध्यम हैं। वर्तमान में देश में 29 लाख एसएचजी मौजूद हैं, जिनमें सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में 3 करोड़ 40 लाख से अधिक महिलाओं की सदस्यता है।

स्वयं -सहायता समूह से तात्पर्य स्वयं-शासित, समकक्ष नियंत्रित, समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के अनौपचारिक समूह से है और सामूहिक रूप से सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं।[7]

स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी सूक्ष्म उद्यमों micro enterprises का एक समग्र कार्यक्रम है जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलुओं (All aspects of self employment) को शामिल किया गया है, जिसमें ग्रामीण गरीबों का स्वयं सहायता समूहों में संगठन और उनकी क्षमता निर्माण, गतिविधि समूहों की योजना, बुनियादी ढांचे का निर्माण, बचत की योजना ,उन्हें शिक्षित करना, रोजगार के विभिन्न साधनों से अवगत करना, आदि विभिन्न पहलू समावेशित है।

आज भारत में ऐसे तमाम उदाहरण है जिन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। छोटे-छोटे समूहों ने सामूहिक प्रयास से अपने स्टार्टअप्स (Startups) शुरू किये और धीरे-धीरे भारतीय बाजारों (Indian markets) में अपनी उपस्थिति दर्ज़ करवाने लगे। भारत में, वर्ष 2015 में जब स्टार्टअप इंडिया अभियान Startup India Campaign का ऐलान किया गया था ।

तब से नए लघु और मध्यम व्यवसायों (MSMEs) Small and Medium Businesses की संख्या बढ़ रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्टार्ट-अप के लिए आर्थिक मदद को बढ़ावा देना है ताकि देश के आर्थिक विकास में स्टार्टअप अपनी भूमिका निभाते रहें। इस अभियान ने कई स्मॉल बिज़नेस और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित किया है, जो अधिक रोज़गार सृजन को भी बढ़ावा दे रहे हैं और और राष्ट्र की आर्थिक ग्रोथ में मदद कर रहे हैं।

परिणाम

आज की दुनिया में, यह व्यक्तियों पर निर्भर करता है कि वे अपने वित्त का प्रबंधन कैसे करें और तेजी से जटिल एकीकृत वित्तीय उत्पादों को कैसे नेविगेट करें। यह साबित हो चुका है कि उम्र, शिक्षा, आय, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय और बचत और निवेश की आदतें किसी व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता पर असर डालती हैं। महिलाओं के लिए आत्मविश्वास के साथ-साथ बेहतर आर्थिक सुरक्षा और अधिक स्वतंत्रता महिलाओं की वित्तीय साक्षरता में वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम है। आर्थिक स्वतंत्रता में अंतर दोनों लिंगों में उम्र और वैवाहिक स्थिति के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध पाया गया है।

वित्तीय साक्षरता क्यों आवश्यक है?

किसी व्यक्ति का आर्थिक सशक्तिकरण तब बढ़ता है जब वह अपने आर्थिक कल्याण की जिम्मेदारी लेने के लिए आवश्यक जानकारी, संसाधन और आत्म-आश्वासन प्राप्त करता है। पैसा कहाँ से आता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को उचित स्रोत के सामने रखना चाहिए। जीविकोपार्जन का संबंध नैतिकता से है, जबकि इसे समझदारी से खर्च करने का संबंध कानून से है। एक व्यक्ति वित्तीय और आर्थिक साक्षरता विकसित करके अपने द्वारा कमाए गए धन और खर्च किए गए धन के लाभों का बेहतर आनंद ले सकता है, जो हमारे आधुनिक समाज में एक आवश्यकता बन गई

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.379 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 6, November 2022 |

है।[8] वित्तीय और आर्थिक साक्षरता किसी व्यक्ति को उसके द्वारा कमाए गए धन और खर्च किए गए धन का सही लाभ उठाने में मदद करती है।

कई भारतीय महिलाओं को कई सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके लिए वित्तीय रूप से साक्षर बनना मुश्किल हो जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि यह महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को पुरुषों के समान वित्तीय निर्णय लेने की समान शक्ति दी जाए। सरकारी प्रयासों के बावजूद, आर्थिक रूप से साक्षर वयस्कों के प्रतिशत में महत्वपूर्ण लैंगिक असमानता बनी हुई है। इसलिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, और महिलाओं की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए। महिलाओं की वित्तीय साक्षरता से न केवल महिलाओं को स्वायत्तता और एजेंसी हासिल करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

भारत में महिलाओं की वित्तीय साक्षरता में योगदान देने वाले कारक

ऐसे कई कारक हैं जो भारतीय महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता के स्तर को प्रभावित करते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण तत्वों की चर्चा इस प्रकार है:

अपने दम पर काम करने में सक्षम न होना: कई विचारधाराएँ लैंगिक समानता की वकालत करती हैं, फिर भी व्यवहार में, महिलाओं को पुरुषों द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता का अभाव है। समस्या की जड़ यह है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर वित्तीय स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश निर्णय लेते समय हमेशा पूरे परिवार को ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि अर्थशास्त्र के बजाय सामाजिक जिम्मेदारी, ऐसे नीति विकल्पों को नियंत्रित करती है। महिलाएं अपने घरों में शांति बनाए रखने के लिए अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का त्याग कर देती हैं और अक्सर अपने पैसे का केवल एक छोटा सा हिस्सा अपनी जरूरतों और चाहतों पर खर्च करती हैं।

सांस्कृतिक मानदंड और अपेक्षाएँ: महिलाओं की वित्तीय शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने में बाधाओं में से एक सांस्कृतिक संदर्भ है जिसमें इसे वितरित किया जाता है। कुछ समाजों में, महिलाओं को पारिवारिक वित्त संभालने की अनुमति नहीं है। पारंपरिक लिंग भूमिकाओं में पुरुष वित्त संभालते हैं और महिलाएं बच्चों और घर की देखभाल करती हैं। वे खुद पर विश्वास खो देते हैं और इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत वित्त के बारे में जानने के उनके प्रयासों में बाधा आती है।

विशेष रूप से महिलाओं के लिए अपर्याप्त वित्तीय पहल: अधिकांश बैंक केवल मानक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने या उनके लिए नवीन बैंकिंग कार्यक्रम बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते हैं। इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए उच्च और कठिन शर्तों के कारण, महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और आवश्यक शब्दावली सीखने से हतोत्साहित होती हैं। महिलाओं की वित्तीय साक्षरता में एक और बाधा उन उत्पादों का प्रचलन है जो घरों के बजाय केवल व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।[9]

पहुँच संबंधी समस्याएँ: चूँकि अधिकांश बैंक उस स्थान के पास सुविधाजनक स्थान पर नहीं हैं जहाँ महिलाएँ रहती हैं या अपना व्यवसाय चलाती हैं, इसलिए शाखा में जाना उनके लिए महंगा और असुविधाजनक हो सकता है। इस समस्या से ज्यादातर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को जूझना पड़ता है।

उपलब्ध वित्तीय विकल्पों और आवश्यक कदमों की कम जानकारी: कई वित्तीय संगठन मुख्यधारा के मीडिया और बिलबोर्ड के माध्यम से अपनी सेवाओं का विज्ञापन करते हैं, हालांकि अधिकांश महिलाएं अभी भी अपने विकल्पों के बारे में अंधेरे में हैं। समझ की कमी किसी के पैसे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के तरीके को सीखने में बाधा है। निवेश और वित्तीय नियोजन में सहायता के लिए अपने जीवनसाथी या परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भरता के कारण वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने में उनकी असमर्थता बाधित होती है।

ऐसे लाभ जो कम आकर्षक हैं: कई महिलाएं ऋण पर ली जाने वाली उच्च ब्याज दरों, चालू खातों को रखने और संचालित करने के लिए ली जाने वाली उच्च फीस और भुगतान की जाने वाली कम ब्याज दरों के कारण इन सेवाओं का उपयोग करने से बचती हैं। बचत खातों में जमा किया गया.

प्रारंभिक शिक्षा का अभाव: भारतीय महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में काफी कम है। कई संस्कृतियाँ और समुदाय उच्च शिक्षा प्राप्त करने या प्राप्त करने वाली महिलाओं का समर्थन नहीं करते हैं। भारत में महिलाओं की वित्तीय साक्षरता के निम्न स्तर का कारण बुनियादी शिक्षा और कंप्यूटर साक्षरता की कमी भी है।

अपर्याप्त वित्तीय संसाधन: भारत में बहुत सारी महिलाएँ हैं जो काम नहीं करती हैं। वे वित्तीय सहायता के लिए अपने पिता या पति पर निर्भर रहती हैं क्योंकि वे काम करने में असमर्थ हैं। इससे परिवार की वित्तीय स्थिति के संबंध में स्वयं निर्णय लेने की उनकी क्षमता भी सीमित हो जाती है।

दुनिया भर में, महिलाओं और लड़कियों को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते समय महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के बिना, महिलाओं और लड़कियों के पास नौकरी के कम अवसर होते हैं, वे यौन हिंसा और तस्करी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, और उनके परिवारों के लिए कमाई की संभावना कम होती है। महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा में निवेश से होने वाले आर्थिक और सामाजिक लाभ पर्याप्त हैं। परिणामस्वरूप, महिलाएं और लड़कियां खुद को, अपने परिवार और

अपने समुदाय को बेहतर बनाने में सक्षम हैं। बुनियादी शिक्षा तक पहुंच पाने में सक्षम होने से उन्हें अपने भविष्य के बारे में शिक्षित विकल्प चुनने और अपने समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने का अधिकार मिलता है।[10]

महिलाओं की वित्तीय साक्षरता विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, जो विभिन्न संस्थानों द्वारा विकसित नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की सहायता से विकास की धारणाओं का आकलन करना है। विश्व स्तर पर, ऐसे कई गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी संगठन और सरकारी संस्थान हैं जो प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका मानना है कि महिलाओं को अपनी परिस्थितियों के साथ-साथ अपने अधिकारों और क्षमताओं के बारे में सीखने से लाभ होगा।

महिलाओं की अपने बच्चों में वित्तीय आदतों और क्षमताओं के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वे बच्चों के पालन-पोषण की प्राथमिक ज़िम्मेदारी के साथ-साथ घरेलू संसाधनों के आवंटन पर आवश्यक और दैनिक निर्णय लेती हैं। उन्हें न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आर्थिक रूप से स्थिर होने की जरूरत है। कामकाजी महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन 15% कम कमाती हैं। महिलाओं को अपनी उच्च जीवन प्रत्याशा, कम कामकाजी जीवन और कम औसत वेतन के कारण होने वाले बड़े वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता होती है, जो सभी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना अधिक कठिन बना देते हैं। महिलाओं को, घर के अंदर और बाहर, आर्थिक गतिविधियों और वित्तीय निर्णय लेने में पूरी तरह से भाग लेने के लिए जानकारी, आत्मविश्वास हासिल करने की आवश्यकता है।

महिलाओं की वित्तीय साक्षरता की क्या आवश्यकता है?
"अपने जीवन का प्रबंधन करें और अपने अधिकारों का दावा करें" ऊपर दी गई सशक्तिकरण की परिभाषा का एक प्रमुख घटक है। अपने स्वयं के वित्त पर नियंत्रण पाने से न केवल आत्म-सम्मान बढ़ता है, बल्कि महिलाओं को परिवार और सामुदायिक निर्णय लेने में भी समान दर्जा मिलता है।
यह न केवल कम आय वाले क्षेत्रों की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो धनी पृष्ठभूमि से आते हैं जहां महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं है।[11]

क्या होता है जब महिलाओं में वित्तीय स्वतंत्रता की कमी होती है?
जब महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है, तो वे अपने जीवन की अधिक जिम्मेदारी महसूस करती हैं। जो महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं, उनके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 70% भारतीय महिलाएं हर साल घरेलू हिंसा का अनुभव करती हैं। पैसे तक पहुंच को प्रतिबंधित करना इस प्रकार की हिंसा को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले "नियंत्रित व्यवहार" का एक उदाहरण है। परिणामस्वरूप, घरेलू हिंसा के पीड़ित जिनके पास वित्तीय संसाधनों की कमी है, वे अपने साथ दुर्व्यवहार करने वाले को छोड़ने में सक्षम नहीं होते हैं और अक्सर उसके साथ एक ही घर में रहने के लिए मजबूर होते हैं।

यदि माता-पिता को लगता है कि उनकी बेटियों का स्वतंत्र होने से कोई लेना-देना नहीं है, तो वे अपनी बेटियों की शिक्षा को नजरअंदाज करना चुन सकते हैं। यह एक बहुत ही चिंताजनक आँकड़ा है: ग्रामीण भारत में, प्रत्येक सौ में से केवल एक लड़की हाई स्कूल पूरी करती है।

क्या होता है जब महिलाएं वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर लेती हैं?
जब पुरुषों से तुलना की जाती है, जो आम तौर पर अपनी आय का 30% से 40% के बीच निवेश करते हैं, तो अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाएं अपनी कमाई का 90% अपने घरों में पुनः निवेश करती हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षों में लिंग को लेकर कई चर्चाएँ होती रही हैं। ये विवाद ज्यादातर समाज में महिलाओं की भूमिका, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, लैंगिक समानता आदि से संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में, भारत में महिलाओं ने हमेशा एक विरोधाभासी स्थिति पर कब्जा कर लिया है। इस तथ्य के बावजूद कि आधुनिक समाज में महिलाएं धीरे-धीरे अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने लगी हैं और राजनीति, खेल, मनोरंजन, साहित्य और प्रौद्योगिकी सहित हर पेशे में हावी हो रही हैं, फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें वे पुरुषों से पीछे हैं। व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन ऐसा ही एक क्षेत्र है। यह देखा गया है कि जब घरेलू खर्च और बचत की बात आती है तो महिलाएं छोटे पैमाने पर बेहतर धन प्रबंधक होती हैं, लेकिन कई महिलाएं, विशेष रूप से कामकाजी महिलाएं, अपने दीर्घकालिक वित्त और सेवानिवृत्ति योजना को उनके हाथों में छोड़ने से संतुष्ट दिखाई देती हैं। उनके पिता या जीवनसाथी का. दूसरे शब्दों में, उनका व्यक्तिगत वित्त उनके घरेलू वित्त के समान दक्षता के स्तर को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इस समस्या का मुख्य कारण महिलाओं में वित्तीय ज्ञान की कमी है।

यह देखते हुए कि भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है, यह अनुचित होगा यदि केवल शेष आधी आबादी ही वित्तीय निर्णय ले। इसके अलावा, कई सैद्धांतिक विचार इस धारणा का समर्थन करते हैं कि तार्किक वित्तीय निर्णय लेने के लिए महिलाओं को वित्तीय रूप से साक्षर होना चाहिए। कुछ तर्क नीचे सूचीबद्ध हैं:

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.379 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 6, November 2022 |

औसत जीवन काल में वृद्धि: एक अध्ययन से पता चलता है कि कई देशों में, गरीब और विकसित देशों सहित, महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन पांच साल अधिक जीवित रहती हैं। इसलिए, महिलाओं को किसी भी वित्तीय कठिनाई से खुद को सुरक्षित रखने के लिए वित्तीय नियोजन और निवेश के अवसरों के बारे में जितना संभव हो उतना सीखना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका और औद्योगिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों से पता चला है कि वृद्ध एकल पुरुषों और विवाहित जोड़ों की तुलना में मध्यम वर्ग में वृद्ध एकल महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं, इसलिए समय के साथ अज्ञानता के परिणाम अधिक बड़े हो सकते हैं।[12]
आर्थिक विस्तार: महिला निवेशक समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे बाजार में तरलता बढ़ाती हैं और वाणिज्य के लिए आर्थिक आधार को व्यापक बनाती हैं। यदि अधिक महिलाएँ वित्तीय रूप से साक्षर होतीं, तो यह एक वास्तविकता होती।
आत्मनिर्भर: यदि महिलाओं को कभी भी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की आशा है तो उन्हें व्यक्तिगत वित्त की मूल बातें सीखने की जरूरत है। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार होगा क्योंकि वे आर्थिक स्वायत्तता के मामले में पुरुषों के बराबर होंगी।
उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति: वित्तीय साक्षरता प्राप्त करने से व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को शिकारी ऋण प्रथाओं और वित्तीय शोषण के अन्य रूपों से बचाने में मदद मिलेगी।
पारिवारिक कल्याण और कल्याण: ऐसा माना जाता है कि वित्तीय साक्षरता में लैंगिक असमानताएं इस बात को प्रभावित करती हैं कि परिवार के पैसे के बारे में निर्णय कौन लेता है। पारिवारिक इकाई का स्वास्थ्य इस तथ्य से प्रभावित होता है कि पुरुष और महिलाएं घरेलू संसाधनों का आवंटन अलग-अलग तरीकों से करते हैं। कई अलग-अलग देशों में किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों से पता चलता है कि परिवार शून्य में निर्णय नहीं लेते हैं। इसके बजाय, यह पता चला है कि जब घरेलू संसाधन महिलाओं के हाथों में होते हैं, तो उन्हें परिवार, विशेषकर बच्चों के कल्याण पर खर्च किए जाने की अधिक संभावना होती है।

जब महिलाओं की वित्तीय साक्षरता की बात आती है तो भारत में अभी भी एक महत्वपूर्ण लिंग अंतर है, इस तथ्य के बावजूद कि महिलाओं के लिए पैसे के बारे में सीखना और वित्तीय योजनाएं स्थापित करना महत्वपूर्ण है। हालाँकि भारत में महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए कुछ सकारात्मक सरकारी हस्तक्षेप और प्रयास किए गए हैं, फिर भी देश में महिलाओं को अभी भी कई बाधाएँ दूर करनी होंगी।[10]

महिलाओं की वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए सरकारी प्रयास
वित्तीय सेवाओं तक देश की पहुंच बढ़ाने का प्राथमिक साधन वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भारत सरकार ने महिलाओं की वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहल की हैं।
बचत और निवेश व्यवहार को बढ़ावा देकर पूंजी का निर्माण। महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई सरकारी कार्यक्रम स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रव्यापी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के प्रमुख तत्वों में शामिल हैं:
बचत कब शुरू करनी चाहिए?
किसी को निवेश क्यों करना चाहिए?
किसी को बीमा क्यों लेना चाहिए?
रिटायर होने के बाद आपको स्थिर आय की आवश्यकता क्यों है?
किसी को नियमित रूप से किस उद्देश्य के लिए पैसा अलग रखना चाहिए?
किसी को व्यापक कवरेज क्यों मिलनी चाहिए?
किसी को बैंकों में निवेश क्यों करना चाहिए?
अपनी उधारी में बाधा क्यों डालें?
वित्तीय संस्थानों से ऋण क्यों लें?
बचत और निवेश कैसे भिन्न हैं?
पैसा कमाने के लिए आपको ऋण क्यों लेना चाहिए?
आपको ऋण क्यों चुकाना है?
आपको समय पर ऋण भुगतान क्यों करना चाहिए?
आपको बीमा की आवश्यकता क्यों महसूस होती है?
वास्तव में ब्याज क्या है? ऋणदाता उच्च ब्याज कैसे वसूलते हैं?[9]

निष्कर्ष

नीचे कुछ सरकारी कार्यक्रम दिए गए हैं जिन्हें हाल ही में लागू किया गया है:
एफएलसीसी (वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट परामर्श केंद्र)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.379 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 6, November 2022 |

भारत सरकार ने देश के वित्तीय समावेशन के समग्र स्तर को बढ़ाने के प्रयास में मुफ्त वित्तीय साक्षरता/शिक्षा प्रदान करने के लिए एफएलसीसी की स्थापना की है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

यह कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है जिसका लक्ष्य सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाना है।

सुकन्या समृद्धि योजना

विशेष रूप से, प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि परिवार के धन और संपत्ति का उचित हिस्सा पाने के लिए लड़की को लड़के की तुलना में अधिक समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी और महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा।[8]

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

पीएमजेडीवाई की शुरूआत देश के वित्तीय समावेशन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। यह यह सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल है कि देश के सभी घरों में बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो। "प्रधानमंत्री जन-धन योजना" (पीएमजेडीवाई) का लक्ष्य कमजोर वर्गों और निम्न-आय समूहों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है, जैसे कि बुनियादी बचत बैंक खाता, आवश्यकता-आधारित सेवाओं तक पहुंच। क्रेडिट, प्रेषण सुविधा, बीमा, और एक पेंशन। इस स्तर की व्याप्ति को प्राप्त करने के लिए व्यापक वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता है।

इस उद्देश्य से, सरकार वित्तीय प्रणाली तक पहुंच बढ़ाने के लिए वित्तीय शिक्षा के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष उपाय कर रही है।

एनसीएफई का गठन

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) ने राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) की देखरेख के लिए वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर एक तकनीकी समूह का गठन किया है, जो वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई) को लागू करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), भारतीय पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), और राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) इस बोर्ड (एनआईएसएम) में सभी के प्रतिनिधि हैं। राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) की प्राथमिक जिम्मेदारी वित्तीय साक्षरता संसाधनों का विकास और प्रसार करना और सभी जनसांख्यिकी और आय स्तरों को लक्षित करते हुए देश के सभी क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता अभियान आयोजित करना है।

सभी नागरिकों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के सरकार के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, महिलाओं को अभी भी धन प्रबंधन के बारे में सीखने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उन्हें अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने से रोकती है।[7]

भारत में महिलाओं की वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए कदम· प्रशिक्षण एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग महिलाओं को धन और वित्त के बारे में सीखने में आजीवन रुचि रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है। कम आय वाले परिवारों की महिलाओं और कम शिक्षा वाली महिलाओं को इस प्रशिक्षण से विशेष रूप से लाभ होता है। अपनी शिक्षा में अंतर के परिणामस्वरूप, अधिकांश महिलाएँ वित्तीय चिंताओं से निपटने से बचती हैं। इसलिए, महिलाओं को अपने वित्तीय मामलों को संभालने में अधिक सक्षम बनाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करना महत्वपूर्ण है।[5]

· बजट बनाना, बचत करना, वित्तीय सेवाओं को समझना, ऋण प्रबंधन, वित्तीय रूप से बातचीत करना और निवेश करना वित्तीय साक्षरता के कई क्षेत्रों में से कुछ हैं जिनकी महिलाओं को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफल होने के लिए आवश्यकता है। इसलिए, छात्रों को विभिन्न कार्यक्रमों और कक्षाओं के माध्यम से पैसे के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। बुनियादी बचत, ऋण, बीमा और पेंशन सभी जीवन के आवश्यक घटक हैं जिन पर वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों में जोर दिया जाना चाहिए।

· दूरी महिलाओं के सामने एक और बाधा है क्योंकि कई बैंक और क्रेडिट यूनियन उस स्थान के आसपास स्थित नहीं हैं जहां महिलाएं रहती हैं। बैंकों, डाकघरों, बीमा एजेंसियों आदि जैसे वित्तीय संस्थानों को इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जहां लोग रहते हैं, उसके करीब दुकान स्थापित करने की आवश्यकता है। यही बात महिलाओं पर भी लागू होती है, जो अब बैंक प्रतिनिधि बनकर अधिक पैसा कमा सकती हैं।

· आईसीटी जैसे प्रौद्योगिकी सुधारों का उपयोग महिलाओं को अधिक वित्तीय रूप से साक्षर बनने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। वित्तीय शिक्षा और सूचना तक पहुंच में काफी सुधार हुआ है क्योंकि मोबाइल तकनीक गरीबों के लिए अधिक सुलभ हो गई है। देश में वित्तीय साक्षरता निर्देश के प्रसार को टेलीविजन, प्रकाशन और इंटरनेट सहित मीडिया आउटलेट्स के उपयोग से सहायता मिल सकती है।

· ई-लर्निंग में प्रशिक्षण, सूचना साझा करने और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार के लिए एक उपयोगी शैक्षणिक साधन बनने की क्षमता है।

· पुरुष-प्रधान भारतीय संस्कृति आधुनिक भारतीय महिलाओं के लिए प्राथमिक बाधा है। कई महिलाओं के पास वित्तीय शिक्षा के लिए विश्वसनीय संसाधनों तक पहुंच का अभाव है। वे केवल अपने परिवार की परंपराओं का पालन कर रहे हैं। भारत में महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे घर पर रहें और अपने परिवार की देखभाल करें; कार्यस्थल या घर के वित्त में उनकी बहुत कम भूमिका होती है। इसलिए, महिलाओं की वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता है।
· यदि महिलाओं को अधिक आकर्षक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई गईं, जिनमें ऋण पर कम ब्याज दरें, जमा पर उच्च ब्याज दरें, कर छूट आदि शामिल हैं, तो अधिक महिलाएं वित्तीय गतिविधियों में भाग लेने के लिए आकर्षित होंगी। इस तरह के प्रोत्साहन बैंकों जैसे कई वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन वे निवेश करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यदि महिलाओं को अपनी वित्तीय साक्षरता बढ़ानी है, तो उन्हें प्रासंगिक वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने और उनका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार, सरकार को महिलाओं को अधिक लाभ प्रदान करने और अधिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए जो महिलाओं को वित्तीय रूप से अधिक समझदार होने के लिए प्रोत्साहित करेगा।[3]
· जब अधिक कॉलेज और संस्थान उपलब्ध होंगे, तो अधिक महिलाओं को वित्तीय शिक्षा तक पहुंच मिलेगी। भारत में कुछ विश्वविद्यालय महिलाओं को व्यक्तिगत वित्त के बारे में शिक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसा ही एक विश्वविद्यालय है वनस्थली विद्यापीठ।

भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बढ़ते उदारीकरण के परिणामस्वरूप उनकी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।[1] औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। यह सच है कि भारत में महिलाएं अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर रही हैं, लेकिन केवल कुछ ही परिवारों में उन्हें स्वयं महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। हालाँकि अधिकांश महिलाएँ घर पर महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय नहीं लेती हैं, पेशेवर महिलाएँ, विशेष रूप से प्रमुख शहरों में, हर जगह की महिलाओं के लिए एक शानदार उदाहरण स्थापित करती हैं। शहर में महिलाएं न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार के लिए भी निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत में युवा लड़कियों को शिक्षित करने पर जोर देने के कारण महिलाएं अब उच्च जीवन स्तर का आनंद ले रही हैं। तथापि,
परिणामस्वरूप, देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि निगम वैकल्पिक निवेश विकल्पों को संबोधित करते हुए कई जागरूकता कार्यक्रम जारी करें। उन्हें उन अत्याधुनिक बैंकिंग विकल्पों से अवगत कराया जाना चाहिए जो उनके लिए उपलब्ध हैं। महिलाओं की वित्तीय साक्षरता के अलावा, इससे घरेलू बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को विस्तार और फलने-फूलने में मदद मिलेगी।[2]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. "Women's Empowerment" (PDF). मूल (PDF) से 12 मई 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अगस्त 2017.
2. ↑ "Women's Empowerment". मूल से 10 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अगस्त 2017.
3. ↑ "Definition: Women Empowerment". मूल से 25 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अगस्त 2017.
4. कबीर, नैला। "लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण: तीसरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य 1 का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण।" लिंग एवं विकास 13.1 (2005): 13-24।
5. ^ मोसेडेल, सारा (1 मार्च, 2005)। "महिला सशक्तिकरण का आकलन: एक वैचारिक ढांचे की ओर"। अंतर्राष्ट्रीय विकास जर्नल । 17 (2): 243-257. doi : 10.1002/jid.1212 । आईएसएसएन 1099-1328 .
6. ^ बेयेह, एंडलकैच्यू (जनवरी 2016)। "इथियोपिया के सतत विकास में महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता हासिल करने की भूमिका" । प्रशांत विज्ञान समीक्षा बी: मानविकी और सामाजिक विज्ञान । 2 (1): 38. doi : 10.1016/j.psrb.2016.09.013 ।
7. ^ ऑक्सफैम (आगामी), "महिला आर्थिक सशक्तिकरण संकल्पनात्मक ढांचा"
8. ^ बैडेन, सैली; गोएट, ऐनी मैरी (जुलाई 1997)। "किसे ज़रूरत है [सेक्स] जब आप कर सकते हैं [लिंग]? बीजिंग में लिंग पर परस्पर विरोधी प्रवचन"। नारीवादी समीक्षा । 56 (1): 3-25. डीओआई : 10.1057/fr.1997.13 । आईएसएसएन 0141-7789 . एस2सीआईडी 143326556 ।
9. ^ लोपेज़, अल्वारेज़ (2013)। "अनसुनी चीखों से लेकर शक्तिशाली आवाज़ों तक: फिलीपींस में महिला राजनीतिक सशक्तिकरण का एक केस अध्ययन"। सांख्यिकी पर 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीएस) ईडीएसए शांगरी-ला होटल, मांडलुयॉन्ग शहर 1-2 अक्टूबर, 2013 ।
10. ^ "महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए नवाचार" । आईसीआरडब्ल्यू | जुनून । सबूत। शक्ति । 20 मई, 2021 को मूल से संग्रहीत । 20 मई 2021 को पुनःप्राप्त .

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.379 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 6, November 2022 |

11. ^ डेनेउलिन, सेवरिन; लीला शाहनी, संपा. (2009)। "मानव विकास और क्षमता दृष्टिकोण का एक परिचय: स्वतंत्रता और एजेंसी" (पीडीएफ) । स्टर्लिंग, वीए: अर्थस्कैन। 16 जून 2016 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 1 सितंबर 2016 को लिया गया ।
12. ^ गुप्ता, कमला; येसुडियन, पी. प्रिंसी (2006)। "भारत में महिला सशक्तिकरण का साक्ष्य: सामाजिक-स्थानिक असमानताओं का एक अध्ययन"। जियोजर्नल । 65 (4): 365-380.